

भारत का सुरक्षा और विनियम बोर्ड

बनाम

उदयंत मल्होत्रा

(सिविल अपील संख्या 2981-2982/2020)

18 नवंबर, 2020

[न्यायाधिपति डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, न्यायाधिपति इंदू मल्होत्रा और न्यायाधिपति
इंद्रा बनर्जी]

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 - धारा 19 आर /डब्लू धारा 11(1), 11(4)(डी), 11(4ए), 11(5) और 11बी - सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम 2015 - आरईजीएन 10 - यह आरोप लगाया गया था कि कंपनी के प्रतिवादी-सीईओ और प्रबंध निदेशक ने 24.10.2016 को कंपनी के 51,000 शेयर बेचे थे, उन्हें मूल्य संवेदनशील जानकारी, अर्थात् 30.09.2016 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की जानकारी थी - बाद में, कंपनी के शेयरों की कीमत में भारी कमी आई - प्रतिवादी के खिलाफ आरोप यह था कि मूल्य संवेदनशील जानकारी होने के कारण, उसने शेयर बेचे थे और इस प्रकार, एक अनुमानित लाभ कमाया था या एक अनुमानित हानि को टाल दिया था - मामला बन गया 2017 में जांच का विषय और प्रतिवादी को 28.11.2019 को जानकारी के लिए बुलाया गया था - पूर्णकालिक सदस्य ने 15.06.2020 को एक पक्षीय आदेश पारित किया - हालांकि, प्राधिकरण ने माना कि उसे अत्यधिक तात्कालिकता का कोई मामला नहीं मिला, जिसकी आवश्यकता थी सुविधा के संतुलन या अपूरणीय क्षति पर विचार किए बिना केवल प्रथम दृष्टया मामले पर पहुंचने पर कि प्रतिवादी एक अंदरूनी सूत्र था, जैसा कि

विनियम 2015 में परिभाषित है, एक पक्षीय अंतरिम आदेश पारित करें - माना गया: तथ्यों पर, ट्रिब्यूनल आने में सही था इस निष्कर्ष पर कि चूंकि जांच 2017 से लंबित थी और जानकारी 28.11.2019 को प्रदान की गई थी, पूर्णकालिक सदस्य द्वारा जारी किए गए प्रकृति के एक पक्षीय अंतरिम आदेश को पारित करने की कोई तात्कालिकता नहीं थी - यह इस पृष्ठभूमि में था , कि प्राधिकरण ने उचित मामलों में एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित करने की सेबी की शक्ति की पुष्टि करते हुए कहा कि इसका प्रयोग "केवल अत्यधिक जरूरी मामलों में" किया जाना चाहिए - इस प्रकार, निष्कर्ष से भिन्न दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं है मामले के तथ्यों पर ट्रिब्यूनल की - हालाँकि, सेबी की शक्तियों पर ट्रिब्यूनल द्वारा जो व्याख्या की गई है, उसे किसी अन्य मामले में मिसाल के रूप में पेश नहीं किया जाएगा - तदनुसार, अपीलों का निपटारा किया जाता है।

नॉर्थ एंड फूड्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (2019 की अपील 80 पर प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा 12.03.2019 को निर्णय लिया गया) - संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2981-82/2020

अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई की अपील संख्या 145/2020 में प्रतिभूति के निर्णय और आदेश दिनांक 27.06.2020 से

तुषार मेहता, एसजी, महफूज ए नाज़की, अविनाश त्रिपाठी, अपीलकर्ता के वकील।

अमित सिब्बल, वरिष्ठ वकील, सोनल जैन, इशकरण सिंह, प्रतिवादी के वकील।

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय सुनाया गया:

1. ये वैधानिक अपीलें भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड^१ द्वारा प्रतिभूति और विनियम अधिनियम की धारा 152 के तहत स्थापित की गई हैं।

भारतीय विनियम बोर्ड अधिनियम 1992^२ अपील 27 जून 2020 और 23 जुलाई 2020 को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण^३ द्वारा पारित आदेशों से उत्पन्न होती है। न्यायाधिकरण ने धारा 19 के तहत सेबी के पूर्णकालिक सदस्य द्वारा पारित 15 जून 2020 के एक अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया। सेबी अधिनियम की धारा 11(1), 11(4)(डी), 11(4ए), 11(5) और 11बी को सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम 2015 के विनियम 10 के साथ पढ़ा जाए।

2. अंतरिम आदेश द्वारा, पूर्णकालिक सदस्य ने 3,83,16,230.73 रुपये की राशि निर्धारित की, जो अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी पर डायनेमेटिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयरों में प्रतिवादी द्वारा किए गए व्यापार के कारण होने वाली अनुमानित हानि से बचने की मांग की गई थी। .

प्रतिवादी को पूर्णकालिक सदस्य द्वारा एस्करो खाते में राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था

3. वर्तमान अपीलों के प्रयोजन के लिए, तथ्य एक संकीर्ण दायरे में हैं। प्रतिवादी प्रश्नाधीन कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक है। यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 24 अक्टूबर 2016 को कंपनी के 51,000 शेयर बेचे थे, जबकि उन्हें मूल्य संवेदनशील जानकारी, अर्थात् 30 सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की जानकारी थी। यह आरोप लगाया गया था कि वित्तीय परिणामों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। 11 नवंबर 2016 को निदेशकों की नियुक्ति, जिसके बाद कंपनी के शेयरों की कीमत में भारी कमी आई। प्रतिवादी के खिलाफ आरोप यह था कि मूल्य संवेदनशील जानकारी होने और एक जुड़े हुए व्यक्ति होने के नाते, उसने शेयर बेचे थे और इस प्रकार, एक अनुमानित लाभ कमाया था या

एक अनुमानित हानि को टाल दिया था। प्रतिवादी द्वारा की गई बिक्री 2017 में एक जांच का विषय थी। रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि जांच टीम ने 28 नवंबर 2019 को प्रतिवादी से जानकारी मांगी थी। पूर्णकालिक सदस्य ने 15 जून 2020 को एक पक्षीय आदेश पारित किया।

4. प्राधिकरण के समक्ष, प्रतिवादी द्वारा यह आग्रह किया गया था कि लगभग तीन साल पहले किए गए व्यापार के संबंध में प्रतिवादी के खिलाफ एक पक्षीय आदेश पारित करने की कोई जल्दी नहीं थी और जमा राशि की आवश्यकता में अपीलकर्ता की एक पक्षीय कार्यवाही थी। महामारी के दौरान मनमाना है। इसका विरोध करते हुए, अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि एकपक्षीय आदेश पारित करने का कारण यह था कि प्रतिवादी द्वारा प्राप्त अनुमानित लाभ के विचलन की संभावना थी। विवादित आदेश में अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में, प्राधिकरण ने नॉर्थ एंड फूड्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 4 में अपने पहले के फैसले पर भरोसा किया। निर्णय के पैराग्राफ 11 में प्राधिकरण ने इस प्रकार कहा:

"11. जैसा कि नॉर्थ एंड फूड्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में आयोजित किया गया है। लिमिटेड (सुप्रा)विशेष रूप से महामारी अवधि के दौरान एक पक्षीय अंतरिम आदेश पारित करने के मामले में कोई वास्तविक तात्कालिकता नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सेबी के पास अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति है और अत्यधिक जरूरी मामलों में सेबी एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित कर सकता है, लेकिन ऐसी शक्तियों का प्रयोग केवल बेहद जरूरी मामलों में ही किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, हमें अत्यधिक तात्कालिकता का कोई मामला नहीं मिला, जिसके कारण प्रतिवादी को केवल प्रथम दृष्टया मामले पर पहुंचने पर एक पक्षीय अंतरिम आदेश पारित करने की आवश्यकता

पड़ी कि अपीलकर्ता सेबी में परिभाषित एक अंदरूनी सूत्र था (अंदरूनी सूत्र का निषेध) ट्रेडिंग) विनियम, 2015 (संक्षेप में 'पीआईटी विनियम') सुविधा के संतुलन या अपूरणीय क्षति पर विचार किए बिना।

5. हमारे विचार से, अपने सामने आए तथ्यों के आधार पर, प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सही था कि चूंकि जांच 2017 से लंबित थी और जानकारी 28 नवंबर 2019 को प्रदान की गई थी, इसलिए एकपक्षीय पारित करने की कोई जल्दी नहीं थी। प्रकृति का अंतरिम आदेश जो पूर्णकालिक सदस्य द्वारा जारी किया गया था। इस पृष्ठभूमि में, प्राधिकरण ने उचित मामलों में पूर्व पक्षीय अंतरिम आदेश पारित करने की सेबी की शक्ति की पुष्टि करते हुए कहा कि इसका प्रयोग "केवल अत्यधिक जरूरी मामलों में" किया जाना चाहिए।

6. तथ्यों पर, जैसा कि वे इस न्यायालय के समक्ष उभरे हैं, हमें मामले के तथ्यों पर प्राधिकरण के निष्कर्ष से भिन्न दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं मिलता है। अत्यधिक सावधानी बरतते हुए, हम स्पष्ट करते हैं कि हम उन तथ्यों पर दृष्टिकोण की पुष्टि कर रहे हैं जो प्राधिकरण के समक्ष अभिलेख से सामने आए हैं।

7. हालाँकि, विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि सेबी को अपील दायर करने के लिए बाध्य होने का कारण सेबी की वैधानिक शक्तियों पर कानून के असर के सवाल पर लागू आदेश में निहित कुछ टिप्पणियाँ हैं। विशेष रूप से, न्यायालय का ध्यान निम्नलिखित अनुच्छेद की ओर आकर्षित किया गया:

"9. ...हमारी राय है कि जब तक इसका निर्णय नहीं लिया जाता और इसकी मात्रा निर्धारित नहीं हो जाती, तब तक वसूली के लिए कोई भी राशि अग्रिम रूप से जमा करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता, जब तक कि की गई कार्रवाई को दिखाने और उचित ठहराने के लिए कुछ

सबूत न हों। समान प्रकृति का आदेश केवल कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान ही पारित किया जा सकता है और ऐसे आदेश कार्यवाही शुरू होने के समय पारित नहीं किए जा सकते हैं।"

8. सेबी अधिनियम की धारा 11(4) सेबी को निम्नलिखित शर्तों में शक्ति प्रदान करती है:

"11. बोर्ड के कार्य:

(4) उप-धारा (1), (2), (2 ए) और (3) और धारा 11बी में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड, एक आदेश द्वारा, कारणों को लिखित रूप में दर्ज कर सकता है। निवेशकों या प्रतिभूति बाजार के हितों के लिए, या तो लंबित जांच या पूछताछ या ऐसी जांच या पूछताछ के पूरा होने पर, निम्नलिखित में से कोई भी उपाय करें, अर्थात्: -

(ए) ***

(बी) ***

(सी) ***

(डी) जांच के अधीन किसी भी लेनदेन के संबंध में आय या प्रतिभूतियों को जब्त करना और बनाए रखना;

9. चूँकि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि प्राधिकरण ने मामले के तथ्यों के आधार पर पूर्णकालिक सदस्य के एकपक्षीय आदेश को इस आधार पर रद्द करना सही था कि इस तरह के आदेश को बनाए रखने के लिए कोई तात्कालिकता नहीं की गई है, यह है इस न्यायालय के लिए यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्राधिकरण द्वारा सेबी की

शक्तियों पर जो व्याख्या की गई है, विशेष रूप से आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ 9 में, जो ऊपर निकाला गया है, उसे किसी अन्य मामले में मिसाल के रूप में उद्धृत नहीं किया जाएगा। सेबी द्वारा पारित आदेश आवश्यक रूप से सेबी अधिनियम की धारा 11(4) के अनुरूप होना चाहिए।

10. उपरोक्त स्पष्टीकरण के साथ, हम सामने आए तथ्यों पर प्राधिकरण के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। तदनुसार अपीलों का निपटारा किया जाता है।

अंकित ज्ञान

अपीलें निस्तारित की गईं।

१ सेबी

२ सेबी अधिनियम

३ प्राधिकरण

४ 12 मार्च 2019 को निर्धारित अपील संख्या 80/2019

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।